भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2750
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार

†2750. **श्रीमती मालविका देवी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) गत वर्ष देश में विशेषकर ओडिशा में और विशेषकर कालाहांडी तथा नुआपाड़ा जिलों में कितने सरकारी विद्यालय शुरू किए गए;
(ग) सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में स्मार्ट कक्षाओं वाले सरकारी विद्यालयों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): सरकार विभिन्न नीतिगत उपायों और कार्यक्रमों जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों में 112 अल्पविकसित जिलों का तेजी से और प्रभावी रूप से परिवर्तन करना है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता या आर्थिक उत्पादकता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण हैं। यह कार्यक्रम पाँच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल

संसाधन, और आधारभूत अवसरंचना के 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर केंद्रित है। शिक्षा में आठ केपीआई शामिल हैं, जो अधिगम परिणामों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक और संस्थागत संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/) के माध्यम से आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले समग्र स्कोर में 30% वेटेज हेतु उत्तरदायी हैं।

इस कार्यक्रम की व्यापक कार्यनीति कोई अतिरिक्त योजना शुरू करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के तहत विकास कार्यों को अभिसरण और सहयोग के माध्यम से आकांक्षी जिलों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए, ताकि केपीआई में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला टीमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों को कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन अनुदान प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से आकांक्षी जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और अन्य सुविधाओं जैसे स्कूल की अवसरंचना और सुविधाओं को सुदृढ़ करने और पूरा करने को प्राथमिकता देती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी), नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों (एनएससीबीएवी) के लिए व्यापक सहायता के साथ-साथ प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से समग्र शिक्षा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों/आकांक्षी जिलों में स्कूल शिक्षा की अवसरंचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ख) देश और ओडिशा, विशेषत: कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में नव स्थापित सरकारी स्कूलों की संख्या तालिका-1 में दी गई है।

तालिका-1 नव स्थापित सरकारी स्कूल

	वर्ष 2021 में कुल सरकारी स्कूल	वर्ष 2022 में स्थापित सरकारी स्कूल	वर्ष 2023 में स्थापित सरकारी स्कूल
भारत	10,22,386	1,576	1,056
ओडिशा	49,072	71	4
कालाहांडी-ओडिशा	2170	-	-
नुआपाड़ा-ओडिशा	904	-	-

स्रोत- यूडाइज+ विभिन्न रिपोर्ट

(ग) और (घ) समग्र शिक्षा योजना के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान है, जिसके तहत देश भर में पाठ्यचर्या आधारित इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल किताबें, आईसीटी प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षा आदि तैयार की जाती हैं और उनके नियोजन से छात्रों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर-सक्षम शिक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकारी स्कूलों में शिक्षण हेतु हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और ई-सामग्री सहायता सहित स्मार्ट कक्षों की स्थापना में सहायता करती है। इसमें प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाओं हेतु 2.40 लाख रुपये का गैर-आवर्ती अनुदान और ई-सामग्री और डिजिटल संसाधनों, बिजली के शुल्क आदि की पूर्ति हेतु प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 38,000 रुपये का आवर्ती अनुदान शामिल है। कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में स्मार्ट कक्षाओं वाले सरकारी स्कूलों की संख्या तालिका-2 में दी गई है।

तालिका-2 ओडिशा में सरकारी स्कूलों की संख्या

	स्मार्ट कक्षा सुविधा वाले सरकारी स्कूल
ओडिशा	12,505
कालाहांडी-ओडिशा	282
नुआपाड़ा-ओडिशा	193

स्रोत- यूडाइज+ 2023-24

****